(iii) M|S. Chetak Construction Ltd., Indore.

(c) The work has not been awarded.

(d) Does not arise.

(e) Yes, Sir.

(f) All tenders have been rejected.

**Designing and engineering of new public sector fertilizer plants**

812. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:

SHRI SUSHIL CHAND MOHUNTA:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Snam Progetti of Italy has virtually taken over the designing and engineering of the new public sector fertiliser plants in the country and that the Project and Development India Ltd. (PDIL) has expressed its concern about it to Government;

(b) if so, what are the reasons for handling over the entire designing and engineering of the new public sector fertiliser plants to an Italian firm; and

(c) to what extent Indian companies are likely to be affected as a result thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF FERTILIZERS (SHRI K. NATWAR SINGH): (a) to (c) Snamprogetti of Italy has provided basic engineering packages for Urea plant for the 2 public sector gas-based fertilizer projects at Thal in Maharashtra and Guna in Madhya Pradesh. The detailed engineering, supervision in construction work, procurement services, etc., were|are mostly being provided by Projects & Development India Ltd. (PDIL), a public sector engineering and consultancy organisation.

**तिलहन के उत्पादन में आत्म-निर्भरता**

813. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तिलहन के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने और खाद्य तेलों के आयात की मात्रा (मीट्रिक टनों में) में कमी करने के लिए अभी तक क्या उपाय किये गए है ;

(ख) क्या यह सच है कि शुरू में आयात किये गये तेल का मूल्य 4 रुपये प्रति किलोग्राम था जो अब बढ़कर 8 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक हो गया है जबकि आयात की गयी कुल मात्रा के आधे से भी अधिक है ; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए गठित की गयी तकनीकी समिति में शामिल किए गए व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उन्हें क्या कार्य सौंपा गया है ?

**कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) :** (क) देश में तिलहनों के उत्पादन में भरपूर वृद्धि करने की दृष्टि से तिलहन उगाने वाले 17 राज्यों में 1984-85 से केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना शुरू की गई है। इसी प्रकार, भारत सरकार ने खाद्य तेलों के आयात को कम से कम करने के लिये अनेक उपाय किये हैं, अर्थात सार्वजनिक वितरण पद्धति/छोटे पैकों की योजना के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और वनस्पति उद्योग को आयातित खाद्य तेलों के आवन्टन में कमी करना, आयातित खाद्य तेलों के निर्गम मूल्यों में वृद्धि करना वनस्पति के विनिर्माण में विकर्षक सरसों के तेल और विलायक के प्रयोग द्वारा निकाले गये तेलों का उपयोग, गौण तेल के उपयोग पर उत्पाद शुल्क में रियायत, वनस्पति के विनिर्माण के लिये "साल" वसा का उपयोग, तिलहनों की उत्पादकता में वृद्धि करने